क्या कहती है भारतीय पानी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट?

डा0 वीरेन्द्र सिंह यादव
प्रवक्ता हिन्दी विभाग
डी.वी. (पी.जी.) कालेज, उरई ।

भारत में पानी की वर्तमान दशा को देखते हुए विश्व बैंक द्वारा बड़ी परियोजनाओं के लिए निवेश एवं पानी के निजीकरण को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है । क्या विश्व बैंक की पानी संकट को लेकर आई रिपोर्ट वास्तव में हमें भविष्य में आने वाले संकट के लिए चौकन्ना कर रही हैं ? या जिस तरह से हम परम्परागत पानी के प्रयोग की शक्तियों को हाशिए पर रखकर दोहन कर रहे हैं उसको देखते हुए यह लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम वास्तव में पानी की किल्लत को लेकर तीसरे विश्वयुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं । क्या विश्व बैंक की भारत पर पानी की कमी पर आई रिपोर्ट वास्तव में निरपेक्ष है या सिर्फ भारत को कमजोर करने की साजिश मात्र? और भी कई अनुत्तरित यक्ष प्रश्न हैं इस बारह पृष्ठ की रिपोर्ट में ! आखिर क्या कहती है विश्व बैंक की पानी पर भारत के बारे में रपट ?

विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि **" भारत आगामी बरसों में पानी को लेकर जबरदस्त संकट से जूझने वाला है । यदि जल प्रबन्धन के तौर तरीके नहीं बदले गये तो हमें आगामी दो दशकों के दौरान पानी की जबरदस्त किल्लत से दो-चार होना पड़ेगा । इस संकट से निपटने के लिए हमारे पास नये बुनियादी ढ़ांचे पर खर्च करने भर का पैसा भी नहीं होगा । इतना ही नहीं, जिस तरह जनसंख्या वृद्धि के साथ पानी की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, उससे निपटना निहायत मुश्किल होगा। "** आधुनिक युग में व्यक्ति के सोचने की दशा

एवं दिशा में परिवर्तन हुआ है और वह मानता है कि अब जमाना नया है इसलिए कार्य करने के तरीके भी नये होने चाहिए, परन्तु ऐसा सोचने वाले लोगों को यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो बातें अच्छी एवं सत्य होती हैं वह कभी नहीं बदलती । इसलिए हम समय के कैलेण्डर से उनको फैशन की तरह न बदलें तो उचित ही होगा ।

विश्व बैंक की पानी पर आई रिपोर्ट को एक तरफ रखकर निरपेक्ष रूप से यदि हम सोंचे तो वास्तविकता यह है कि हजारों वर्षों से भारत में कुंड, सरोवर और पोखरे आम आदमी के जो स्रोत थे उन्हें हमने फैशन की तरह त्यागकर एक तरफ रख दिया है और हम अपनी धरती में लगातार छेद पर छेद करते चले जा रहे हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि हम खेती, उद्योग और पेयजल व्यवस्था का जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं शायद वह इसलिए कि डीजल एवं बिजली के यंत्रों के विकास ने हमें अधिक सोचने पर विवश भी नहीं किया है इसलिए हम भूलते चले गये कि प्रकृति ने जितना कुछ दिया है वह पर्याप्त नहीं है और " हमने पानी के मामले में सब जगह एक सा बर्ताव शुरू कर दिया । रेगिस्तान में भी गेंहूं उगाने लगे, मूंगफली बोने लगे, मिर्च लगाने लगे । पंजाब की फसल को रेगिस्तान में बोने लगे और तटवर्ती प्रदेशों की फसलों को पंजाब-हरियाणा में उगाने लगे, इस तरह से हमने एक किस्म की अराजकता को कबूल किया है क्योंकि हमें लगा कि हम पानी कहीं से भी लाएंगे और इस तरह हमने अपने नीचे के पानी का भी भरपूर दोहन करना शुरू कर दिया । इस हरकत ने हमारे पैर इतने उखाड़ दिए हैं कि हम न सिर्फ परेशान हो चुके हैं बल्कि बैंक की रपटों की तरफ आतुरता से देख भी रहे हैं । " यहां वास्तविकता यह है कि एक अरब से अधिक आबादी वाले भारत में जल संकट अब तक इसलिए नहीं गहराया क्योंकि हम जल प्रबन्धन को नैतिक, आध्यात्मिक और

सामाजिक दृष्टि से देखते थे न कि आर्थिक नजरिए से क्योंकि हमारे धर्मग्रन्थों में नदियों के जल को पवित्र माना जाता था । और इनके प्रति विशेष सहानुभूति लोगों के अन्दर थी, परन्तु आज हमने अपने खाद्यान्न साधन बढ़ाने को होड़ में नियमों की अवहेलना करके पानी का अंधाधुध उपयोग करके चाहे वे किसानों के टयूबवैल हो या शहरी आबादी वाले पानी के स्रोत हों हमने उन्हें जरूरत से ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया है । तभी जो भारत की सिंचाई सम्बन्धी जरूरतों का सत्तर फीसदी और घरेलू जलापूर्ति का अस्सी फीसदी भूजल से पूरा किया जा रहा है । यहाँ वास्तविकता यह है कि इससे तात्कालिक रूप से हम लाभान्वित अवश्य हुए परन्तु हमारा लाभ जितना अधिक बढ़ा उतना ही अधिक हमारा जलस्तर घटता चला गया । इसके पीछे कुछ हद तक सरकारी नियमों को ढीलापन भी उजागर हुआ जैसे कि कई राज्यों में किसानों को बिजली का मुफ्त किया जाना ।

वास्तविकता यह है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट हमें एक तरह से सावधान ही करती है कि यदि हमने अपनी नीतियों एवं प्रबन्धन में सुधार नहीं किया तो वह पानी के प्रबंध और नये ढांचे के लिए भारत को पैसा उपलब्ध नहीं करा पायेगी । हालाँकि विश्व बैंक की पानी रिपोर्ट पर जो निजीकरण की बात है वह हमारी दृष्टि में उचित नहीं है क्योंकि भारत में जहाँ करोड़ों लोगों को दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता, ऐसे में पानी एक गरीब कहाँ से खरीदेगा इसे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है । विश्व बैंक की रिपोर्ट के पीछे कुछ प्रश्न वर्तमान समय में अलग समूहों में उठ रहे हैं और उनका मानना है कि भारत को यह पुनः गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है वहीं दूसरी ओर पानी का निजीकरण करने के आरोप भी लगने के साथ साथ विश्व बैंक पर महाजनी का आरोप भी लग रहा है ! निजीकरण का प्रश्न उठाकर विश्व बैंक शायद यह कहना चाह रही है

कि इससे भारत में पानी की समस्या समाप्त हो जायेगी । लेकिन भारत में यही समस्या ही मुख्य नही है इसके अलावा और भी मुददे हैं जिन पर विश्व बैंक का ध्यान जाना चाहिए । शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास ऐसे महत्वपूर्ण एवं शालीन मुददे हैं जिन पर विश्व बैंक को निहायत ईमानदारी से सोचना चाहिए । विश्व बैंक की रपट को एक ओर रखकर यदि हम स्वयं में अपना आत्म अवलोकन करें तो जल संरक्षण ही पानी के बेहतरी का उचित समाधान हैं इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग शिददत से पानी के प्रति संवेदनशील हों ।

विश्व बैंक की पानी पर आई रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों के बीच चर्चा का केन्द्र बिन्दु बने हुए हैं, वह हैं कि बैंक का भारत के विकास में कोई तात्पर्य नहीं हैं बल्कि विश्व बैंक भारत को कर्ज का भय दिखाकर एक तरह से डरा रही है ताकि उसका कर्ज देने को काम चलता रहे, कयोंकि यह बारह पृष्ठों की जो रिपोर्ट है उसमें बड़े बांधों के बनाने एवं जल प्रबन्धन को लेकर जो सुझाव दिये गये हैं उस पर केवल इतना कहा जा सकता है कि वास्तव में विश्व बैंक की यदि नियत साफ है तो उसे चाहिए कि वह उन प्रोजेक्टों में मिलने वाले धन पर कर्ज माफ कर दे । हाँ रही बात जल की कमी की तो यह जगजाहिर है कि आज पूरी दुनिया में कमोबेश भारत जैसी स्थिति है चाहे वह ब्रिटेन हो या जापान या अमेरिका सभी जगह पानी का दुरूपयोग एवं जल प्रदूषण फैला हुआ है क्योंकि जिस रफ्तार से विश्व में प्राकृति संसाधनों का दोहन हो रहा है उसके लिए वहाँ का कुप्रबंधन ही जिम्मेदार है न कि संसाधन !

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विश्व बैंक की भारत पर पानी की कमी पर आयी रिपोर्ट एक तरह से हमारे सामाजिक ताने-बाने को एक साजिश के तहत कमजोर करने की कोशिश की जा रही है परन्तु दूसरी ओर एक तरह

से यह रिपोर्ट हमें आत्ममूल्यांकन एवं सचेत भी कर रही है क्योंकि वास्तव में पानी की कमी यदि सन 2020 ई0 तक होती है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी नीतियां एवं कार्यक्रम होने चाहिए? भपिष्य के लिए यह एक यक्ष प्रश्न है कि इस पर हमारे नीति नियन्ताओं एवं प्रशासकों को गम्भीरता से सोचना होगा । इन सबके साथ ही देश की सार्वभौमिकता का सम्मान करते हुए, गलत नीतियों की विरोध करने की कुब्बत भी रखनी होगी तभी हमारी वास्तविक कामयाबी एवं सुरक्षित भविष्य होगा ।